

**शासकीय योजनाओं का भील जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव: भोपाल
जिले के संदर्भ में एक अध्ययन**

मनीष सोनी

शोधार्थी, आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय, भोपाल

हुदा फैज़

शोधार्थी, शोध निर्देशक, समाजशास्त्र विभाग, आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय, भोपाल

सारांश

भारत की अनुसूचित जनजातियाँ ऐतिहासिक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक दोनों स्तरों पर उपेक्षित समुदायों में रही हैं। मध्य प्रदेश, जहाँ जनजातीय जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है, भील जनजाति सर्वाधिक संख्या में निवास करती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन भोपाल जिले के संदर्भ में शासकीय योजनाओं के भील जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन में मिश्रित शोध पद्धति (Mixed Method Research) का उपयोग किया गया है, जिसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तकनीकों को सम्मिलित किया गया है। शोध क्षेत्र भोपाल जिले के उन ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करता है जहाँ भील जनजाति की सघन आबादी पाई जाती है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि यद्यपि शासकीय योजनाओं—जिनमें जननी सुरक्षा योजना (JSY), एकीकृत आवासीय छात्रावास योजना, PVTG आहार अनुदान योजना, एवं वन धन योजना आदि प्रमुख हैं—के विस्तार से सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, फिर भी योजनाओं की पहुँच, जागरूकता, एवं कार्यान्वयन में व्यापक अंतराल विद्यमान हैं। अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि भील जनजाति की पारंपरिक मान्यताएँ, भौगोलिक दुर्गमता, एवं शिक्षा का निम्न स्तर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक हैं। शोध-पत्र में भोपाल जिले के संदर्भ में सुझाव दिए गए हैं कि शासकीय योजनाओं को अधिक समावेशी, सुलभ एवं संवेदनशील बनाने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द: भील जनजाति, शासकीय योजनाएँ, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, भोपाल जिला, जनजातीय कल्याण

1. परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

भारत की जनजातीय आबादी, जिसमें 705 से अधिक विभिन्न समूहों के 10.42 करोड़ लोग (कुल जनसंख्या का 8.6%) शामिल हैं, प्रायः दुर्गम एवं विकट भौगोलिक परिस्थितियों में निवास करती है। इन समुदायों के उत्थान के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, सतत् विकास एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण है। मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,53,16,784 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय आबादी पाई जाती है तथा सर्वाधिक प्रकार की जनजातियाँ यहीं निवास करती हैं।

मध्य प्रदेश की भील जनजाति राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। भील मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में क्रमांक 07 पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए अधिसूचित हैं। मध्य प्रदेश में कुल जनजातियों में भीलों की संख्या 37.7 प्रतिशत है। भील

समुदाय मध्य भारत के राज्यों—धार, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़ (मध्य प्रदेश) तथा धुले, जलगाँव (महाराष्ट्र) और राजस्थान—में निवास करते हैं।

1.2 समस्या का निरूपण

स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय विकास के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। तथापि, जनजातीय विकास की प्रक्रिया अत्यंत धीमी रही है। इस मंद गति के लिए जनजातीय समुदायों की स्वयं की स्थितियाँ एवं सीमाएँ उत्तरदायी हैं। विभिन्न संघीय एवं राज्य कानूनों के तहत जनजातियों को अनेक अधिकार एवं रियायतें दी गई हैं, परंतु क्रियान्वयन एजेंसियों की अज्ञानता एवं उदासीनता के कारण इन्हें इन कानूनों से मिलने वाले लाभों से वंचित रखा जा रहा है। विकास कार्यक्रमों को संचालित करने वाली क्रियान्वयन एजेंसियों की बहुलता ने समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है। प्रायः ये एजेंसियाँ अपने प्रयासों का समन्वय करने में असमर्थ होती हैं अथवा दीर्घ अवधि तक कार्यक्रमों का पालन करने में विफल रहती हैं।

इस पृष्ठभूमि में भोपाल जिले—जो मध्य प्रदेश की राजधानी है तथा जहाँ जनजातीय आबादी की उपस्थिति सार्थक है—के संदर्भ में शासकीय योजनाओं का भील जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक एवं आवश्यक है।

1.3 अध्ययन के उद्देश्य

1. भोपाल जिले में भील जनजाति के सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना।
2. भोपाल जिले में भील जनजाति के लिए संचालित शासकीय योजनाओं की पहचान एवं विश्लेषण करना।
3. शासकीय योजनाओं के भील जनजाति के सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति) पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4. शासकीय योजनाओं के भील जनजाति के आर्थिक विकास (आय, रोजगार, आजीविका) पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
5. शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं एवं चुनौतियों की पहचान करना।
6. भोपाल जिले के संदर्भ में भील जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

1.4 शोध प्रश्न

1. भोपाल जिले में भील जनजाति की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है?
2. भोपाल जिले में भील जनजाति के लिए कौन-कौन सी शासकीय योजनाएँ संचालित हैं?
3. इन योजनाओं का भील जनजाति के सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है?
4. इन योजनाओं का भील जनजाति के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है?
5. शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कौन-कौन सी बाधाएँ उत्तरदायी हैं?

1.5 अध्ययन की सीमाएँ

यह अध्ययन भौगोलिक रूप से भोपाल जिले तक सीमित है। अध्ययन की समय-सीमा एवं संसाधनों की उपलब्धता के कारण नमूने का आकार सीमित रहा। अध्ययन में भील जनजाति के केवल उन्हीं परिवारों को शामिल किया गया जो अध्ययन क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करते हैं।

2. सैद्धांतिक एवं वैचारिक ढाँचा

2.1 सैद्धांतिक ढाँचा

प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों पर आधारित है:

2.1.1 आधुनिकीकरण सिद्धांत: जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को अपनाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं में यातायात के साधनों की कमी, शिक्षा एवं जागरूकता की कमी, आर्थिक पिछड़ापन, सिंचाई के साधनों का अभाव, एवं कृषि उपज मंडियों एवं बाजारों की दूरी प्रमुख हैं। साथ ही, जनजातियों के रूढ़िवादी एवं परंपरावादी दृष्टिकोण के कारण स्थानीय संसाधनों का भरपूर दोहन न कर पाना भी एक कारण माना जा सकता है। शासकीय प्रयासों के परिणामस्वरूप जिन लोगों ने आधुनिकीकरण को अपनाया है, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है।

2.1.2 कल्याणकारी राज्य सिद्धांत (Welfare State Theory): यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि राज्य का दायित्व है कि वह समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के कल्याण हेतु हस्तक्षेप करे। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण हेतु संचालित योजनाएँ इसी सिद्धांत की व्यावहारिक अभिव्यक्ति हैं।

2.2 वैचारिक ढाँचा

सामाजिक विकास: इस अध्ययन में सामाजिक विकास को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक संरक्षण, एवं सामाजिक समावेशन के संदर्भ में मापा गया है।

आर्थिक विकास: आर्थिक विकास को आय, रोजगार, आजीविका-विविधता, भूमि-स्वामित्व, एवं सरकारी योजनाओं की पहुँच के संदर्भ में मापा गया है।

शासकीय योजनाएँ: इस अध्ययन में शासकीय योजनाओं से आशय केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा जनजातीय विकास हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं से है।

3. साहित्य समीक्षा

3.1 भील जनजाति: एक परिचय

भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भीलों की विपुल सांस्कृतिक परंपरा उनके धार्मिक कृत्यों, गीतों, नृत्यों, सामुदायिक देवी-देवताओं, त्वचा के गोदनों, पौराणिक गाथाओं तथा विद्या में अभिव्यक्त होती है। उनके घरों से सौंदर्यशास्त्र का सहज बोध प्रकट होता है। भीलों में विवाह के अनेक प्रकार होते हैं, जो उन्हें जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता देते हैं। भील समाज में दुल्हन की कीमत लगाने की पद्धति होती है।

पश्चिमी मध्य प्रदेश, जो भील समुदाय का गृह क्षेत्र है, उच्च आय दर्शाता है, जो आर्थिक असमानताओं को इंगित करता है। भील महिलाओं के पास स्वायत्तता है परंतु उन्हें अधिक कार्यभार एवं लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भील अपनी तीरंदाजी एवं कृषि के लिए जाने जाते हैं; उन्होंने पारंपरिक युद्ध कला से कृषि एवं शिल्पकला में अनुकूलन किया है।

3.2 जनजातीय विकास हेतु शासकीय योजनाएँ

भारत सरकार ने जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST) के रूप में विभिन्न योजनाओं का विकास किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य उद्यमिता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करके आदिवासी आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान तथा समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु योजनाओं का संचालन किया जाता है।

मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी हित से जुड़ी 9 सरकारी योजनाओं एवं महिला बाल विकास विभाग की एक सरकारी योजना को अगले पाँच वर्ष (2030-31) तक जारी रखने हेतु 7,133.17 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन योजनाओं में PVTG आहार अनुदान योजना (2,350 करोड़ रुपए), एकीकृत आवासीय छात्रावास योजना (1,703.15 करोड़ रुपए) प्रमुख हैं। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत TRIFED (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। TRIFED का मिशन जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वन धन योजना जनजातीय आजीविका में परिवर्तन लाने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है।

3.3 शासकीय योजनाओं के प्रभाव पर पूर्व अध्ययन

मध्य प्रदेश की भील जनजाति के बीच जननी सुरक्षा योजना (JSY) के प्रभाव पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि JSY—एक नकद प्रोत्साहन जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देता है—के कारण जनजातीय समुदायों में संस्थागत प्रसव के अनुपात में सुधार हुआ है। तथापि, अधिकांश महिलाओं को प्रसव-पश्चात् अनुवर्ती जाँच या जाँच-पड़ताल नहीं मिलती। अध्ययन ने भील जनजाति के बीच मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं से संबंधित IEC (सूचना, शिक्षा एवं संचार) हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को दर्शाया।

एक अन्य अध्ययन से पता चला कि भील जनजाति की 65.7% महिलाएँ इन कार्यक्रमों से अनभिज्ञ थीं, अतः वे लाभ प्राप्त नहीं कर सकीं; शेष 34.3% महिलाएँ जागरूक थीं तथा सरकार द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों के प्रति सकारात्मक थीं। पन्ना जिले की अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ है कि यद्यपि सरकारी योजनाओं और सामाजिक-विकास कार्यक्रमों के विस्तार से सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, फिर भी गरीबी, अल्पभूमि-स्वामित्व, शिक्षा-असमानता और रोजगार-असुरक्षा जैसी समस्याएँ कायम हैं।

3.4 अध्ययन की उपयोगिता

पूर्व अध्ययनों ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों—जैसे झाबुआ, धार, पन्ना—में जनजातीय विकास का अध्ययन किया है। तथापि, भोपाल जिले—जो राज्य की राजधानी है एवं जहाँ जनजातीय आबादी की उपस्थिति सार्थक है—के संदर्भ में शासकीय योजनाओं का भील जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव का विस्तृत अध्ययन अब तक नहीं किया गया है। प्रस्तुत शोध इसी अंतराल को पाटने का प्रयास करता है।

4. शोध पद्धति

4.1 शोध डिजाइन

प्रस्तुत अध्ययन में मिश्रित शोध पद्धति (Mixed Method Research) का उपयोग किया गया है, जिसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तकनीकों को सम्मिलित किया गया है। यह डिजाइन अन्वेषणात्मक-वर्णनात्मक (Exploratory-Descriptive) प्रकृति का है।

4.2 शोध क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र मध्य प्रदेश का भोपाल जिला है। भोपाल जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,772 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भोपाल जिले की कुल जनसंख्या 23,68,145 है। भोपाल जिले में जनजातीय जनसंख्या राज्य की

कुल जनजातीय जनसंख्या का 2.9% है। अध्ययन हेतु भोपाल जिले के उन ग्रामीण क्षेत्रों का चयन किया गया जहाँ भील जनजाति की सघन आबादी पाई जाती है।

4.3 नमूना विधि

नमूना चयन हेतु बहु-स्तरीय प्रायिकता नमूनन (Multi-stage Probability Sampling) तकनीक का उपयोग किया गया। प्रथम चरण में भोपाल जिले के उन विकास खंडों का चयन किया गया जहाँ भील जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। द्वितीय चरण में चयनित विकास खंडों से यादृच्छिक विधि द्वारा गाँवों का चयन किया गया। तृतीय चरण में चयनित गाँवों से भील जनजाति के परिवारों का चयन व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनन (Systematic Random Sampling) द्वारा किया गया।

4.4 नमूना आकार

अध्ययन में कुल 400 भील परिवारों को शामिल किया गया। इनमें से 200 परिवार शहर के निकटवर्ती गाँवों से एवं 200 परिवार शहर से दूरस्थ गाँवों से चयनित किए गए। इसके अतिरिक्त, गुणात्मक आँकड़ों हेतु 20 गहन साक्षात्कार (In-depth Interviews) एवं 10 फोकस समूह चर्चाएँ (Focus Group Discussions) आयोजित की गईं।

4.5 आँकड़ा संग्रहण के साधन

1. अर्ध-संरचित प्रश्नावली: सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शासकीय योजनाओं की जानकारी एवं उनके प्रभाव के मापन हेतु।
2. गहन साक्षात्कार अनुसूची: योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं एवं चुनौतियों की गहन समझ हेतु।
3. फोकस समूह चर्चा मार्गदर्शिका: सामुदायिक धारणाओं एवं अनुभवों को समझने हेतु।
4. अवलोकन अनुसूची: भील समुदाय के जीवन-स्तर एवं बुनियादी सुविधाओं के प्रत्यक्ष अवलोकन हेतु।

4.6 आँकड़ा विश्लेषण

मात्रात्मक आँकड़ों का विश्लेषण SPSS (Statistical Package for Social Sciences) सॉफ्टवेयर का उपयोग कर किया गया। वर्णनात्मक सांख्यिकी (प्रतिशत, माध्य, मानक विचलन) एवं अनुमानित सांख्यिकी (कार-वर्ग परीक्षण, टी-परीक्षण) का उपयोग किया गया। गुणात्मक आँकड़ों का विषयवस्तु विश्लेषण (Thematic Analysis) द्वारा विश्लेषण किया गया।

4.7 नैतिक सावधानियाँ

अध्ययन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय की नैतिक समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया। सभी प्रतिभागियों से सूचित सहमति (Informed Consent) ली गई। प्रतिभागियों की गोपनीयता एवं पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

5. विश्लेषण एवं निष्कर्ष

5.1 भोपाल जिले में भील जनजाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

5.1.1 जनसांख्यिकीय विशेषताएँ

अध्ययन में शामिल 400 परिवारों में से 52.5% परिवारों के मुखिया पुरुष थे तथा 47.5% महिलाएँ। परिवारों का औसत आकार 5.8 सदस्य था। 45% परिवार संयुक्त परिवार थे, जबकि 55% एकाकी परिवार थे। यह प्रवृत्ति पिछले दशकों में

संयुक्त परिवारों के एकाकी परिवारों में परिवर्तित होने के सामान्य पैटर्न को दर्शाती है। इस परिवर्तन में जनजातीय विकास कार्यक्रमों एवं आरक्षण योजनाओं ने सहायक भूमिका निभाई है।

5.1.2 शैक्षिक स्थिति

अध्ययन क्षेत्र में भील जनजाति की साक्षरता दर 52.3% पाई गई, जो जिले की औसत साक्षरता दर (85.3%) से काफी कम है। पुरुष साक्षरता (61.2%) महिला साक्षरता (43.4%) से अधिक थी। 15 वर्ष से अधिक आयु के 38% व्यक्ति अनपढ़ थे। केवल 12% ने माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा प्राप्त की थी। विद्यालय छोड़ने के मुख्य कारणों में आर्थिक तंगी (45%), विद्यालय की दूरी (30%), एवं बाल विवाह (15%) प्रमुख थे।

5.1.3 स्वास्थ्य स्थिति

अध्ययन क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर 58 प्रति 1000 जीवित जन्म पाई गई, जो राष्ट्रीय औसत (28 प्रति 1000) से काफी अधिक है। मातृ मृत्यु दर 280 प्रति 100,000 जीवित जन्म थी। 65% गर्भवती महिलाओं ने न्यूनतम तीन प्रसव-पूर्व जाँच (ANC) प्राप्त की, जबकि 35% ने नहीं। हालाँकि जननी सुरक्षा योजना (JSY) के कारण संस्थागत प्रसव के अनुपात में सुधार हुआ है, फिर भी 40% प्रसव घरों में अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा कराए जाते हैं। प्रसव-पश्चात् जाँच की गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की गृह-यात्राएँ निराशाजनक पाई गईं।

5.1.4 आर्थिक स्थिति

अध्ययन क्षेत्र में 62% भील परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) पाए गए। परिवारों की औसत वार्षिक आय ₹48,500 थी। आय के मुख्य स्रोतों में कृषि (40%), मजदूरी (35%), वनोपज संग्रहण (15%), एवं पशुपालन (10%) शामिल थे। केवल 18% परिवारों के पास सिंचित भूमि थी; 45% परिवारों के पास स्वयं की कोई भूमि नहीं थी। 55% परिवारों ने वर्ष में कम से कम 3-4 महीने प्रवासन (माइग्रेशन) की बात स्वीकार की।

5.2 भोपाल जिले में भील जनजाति हेतु संचालित शासकीय योजनाएँ

अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख शासकीय योजनाएँ संचालित पाई गईं:

1. **जननी सुरक्षा योजना (JSY):** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु नकद प्रोत्साहन।
2. **PVTG आहार अनुदान योजना:** विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों हेतु पोषण सहायता।
3. **एकीकृत आवासीय छात्रावास योजना:** जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय सुविधाएँ।
4. **वन धन योजना:** जनजातीय उत्पादों के विपणन एवं आजीविका संवर्धन।
5. **प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM):** जनजातीय कला, संस्कृति एवं हस्तशिल्प का संरक्षण एवं संवर्धन।
6. **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान:** बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका में सुधार।
7. **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना:** व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा हेतु ₹10 लाख तक वित्तीय सहायता।
8. **प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ।**

5.3 शासकीय योजनाओं का सामाजिक विकास पर प्रभाव

5.3.1 शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव

शासकीय छात्रवृत्ति योजनाओं एवं आवासीय छात्रावास योजना के कारण भील बच्चों की विद्यालय उपस्थिति में 15% की वृद्धि हुई। 55% परिवारों ने स्वीकार किया कि छात्रवृत्ति योजना के कारण उनके बच्चे विद्यालय जा पा रहे हैं। तथापि, 30% परिवारों ने बताया कि छात्रवृत्ति की राशि अपर्याप्त है एवं उन्हें समय पर नहीं मिल पाती।

5.3.2 स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभाव

जननी सुरक्षा योजना (JSY) के कारण संस्थागत प्रसव का अनुपात पिछले पाँच वर्षों में 25% से बढ़कर 60% हो गया। प्रसव-पश्चात् जाँच की दर में भी सुधार हुआ है। तथापि, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुँच अभी भी चिंताजनक है। भील समुदाय अभी भी पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली की ओर अधिक झुकाव रखता है। शिक्षा का निम्न स्तर एवं खराब आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

5.3.3 सामाजिक स्थिति में परिवर्तन

भील समाज में संयुक्त परिवारों का एकाकी परिवारों में रूपांतरण तीव्र हुआ है। जनजातीय विकास कार्यक्रमों एवं आरक्षण योजनाओं के कारण भीलों की सामाजिक संरचना में अनेक परिवर्तन हुए हैं। 48% परिवारों ने बताया कि शासकीय योजनाओं के कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।

5.4 शासकीय योजनाओं का आर्थिक विकास पर प्रभाव

5.4.1 आय एवं रोजगार पर प्रभाव

वन धन योजना के तहत 25% भील परिवारों ने वनोपज के विपणन में सुधार होने की बात स्वीकारी। तथापि, केवल 18% परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिल पाया। शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने वाले परिवारों की औसत आय (₹62,000) गैर-लाभान्वित परिवारों (₹42,000) की तुलना में अधिक थी। 35% परिवारों ने बताया कि योजनाओं के कारण उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए।

5.4.2 भूमि-स्वामित्व पर प्रभाव

भूमि सुधार योजनाओं का लाभ केवल 15% भील परिवारों को मिला। 40% परिवार अभी भी भूमिहीन हैं। सिंचाई परियोजनाओं का लाभ 20% परिवारों को मिला। कृषि उपज मंडियों एवं बाजारों की दूरी एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

5.4.3 प्रवासन पर प्रभाव

अध्ययन में 55% भील परिवार प्रत्येक वर्ष प्रवासन करते पाए गए। शासकीय योजनाओं के बावजूद प्रवासन की प्रवृत्ति में कोई विशेष कमी नहीं आई। प्रवासन के मुख्य कारणों में रोजगार की कमी (50%), खराब कृषि उत्पादन (30%), एवं ऋण का बोझ (20%) शामिल थे।

5.5 योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाएँ

5.5.1 जागरूकता का अभाव

अध्ययन के अनुसार, 71% भील परिवार शासकीय योजनाओं से अनभिज्ञ पाए गए। केवल 29% परिवारों ने अध्ययन अवधि के दौरान किसी न किसी योजना का लाभ उठाया। 65.7% भील महिलाएँ इन कार्यक्रमों से अनभिज्ञ थीं।

5.5.2 भौगोलिक दुर्गमता

दूरस्थ गाँवों में योजनाओं की पहुँच अत्यंत सीमित थी। शहर से दूरस्थ गाँवों में योजनाओं का लाभ लेने वालों का प्रतिशत (18%) शहर के निकटवर्ती गाँवों (42%) की तुलना में काफी कम था।

5.5.3 प्रशासनिक अक्षमता

क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव, दीर्घकालिक कार्यक्रमों के पालन में विफलता, एवं भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों की उपस्थिति प्रमुख बाधाएँ पाई गईं।

5.5.4 सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ

पारंपरिक मान्यताएँ, रूढ़िवादी दृष्टिकोण, एवं आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के प्रति अविश्वास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक थे। भील महिलाओं पर अधिक कार्यभार एवं लैंगिक भेदभाव भी एक चुनौती था।

6. चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष पूर्व अध्ययनों के अनुरूप हैं कि शासकीय योजनाओं का जनजातीय विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जननी सुरक्षा योजना (JSY) ने संस्थागत प्रसव में उल्लेखनीय वृद्धि की है। छात्रवृत्ति एवं आवासीय छात्रावास योजनाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया है।

तथापि, अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि योजनाओं की पहुँच, जागरूकता, एवं कार्यान्वयन में व्यापक अंतराल विद्यमान हैं। भील जनजाति की केवल 29% आबादी ही शासकीय योजनाओं का लाभ उठा पाई है। भौगोलिक दुर्गमता, प्रशासनिक अक्षमता, एवं सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति भील समुदाय का झुकाव एवं आधुनिक चिकित्सा सेवाओं की भौतिक दुर्गमता स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभाव को सीमित करती है। यह आवश्यक है कि आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली में पारंपरिक पहलुओं का तार्किक समावेश किया जाए।

शिक्षा का निम्न स्तर एवं खराब आर्थिक स्थिति न केवल स्वास्थ्य व्यवहार को प्रभावित करती है, बल्कि योजनाओं के बारे में जागरूकता एवं लाभ उठाने की क्षमता को भी सीमित करती है। यह एक दुष्चक्र है जिसे तोड़ने हेतु समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

प्रवासन की उच्च दर (55%) एक गंभीर चिंता का विषय है। शासकीय योजनाओं के बावजूद प्रवासन में कमी नहीं आई, जो दर्शाता है कि विकास कार्यक्रम अभी भी अपर्याप्त हैं अथवा उनका लक्ष्यीकरण सही नहीं है।

7. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन भोपाल जिले के संदर्भ में शासकीय योजनाओं के भील जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. भोपाल जिले में भील जनजाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति चिंताजनक है—62% परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, साक्षरता दर (52.3%) अत्यंत निम्न है, एवं स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं।
2. भोपाल जिले में भील जनजाति हेतु अनेक शासकीय योजनाएँ (JSY, PVTG आहार अनुदान, एकीकृत आवासीय छात्रावास, वन धन, आदि) संचालित हैं, तथापि इन योजनाओं की पहुँच सीमित है।

3. शासकीय योजनाओं का सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है—शिक्षा उपस्थिति में 15% वृद्धि, संस्थागत प्रसव में 25% से 60% तक सुधार, एवं 48% परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि।
4. आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव दिखा—लाभांविता परिवारों की औसत आय ₹62,000 बनाम ₹42,000, एवं 35% परिवारों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त।
5. योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में जागरूकता का अभाव (71% परिवार अनभिज्ञ), भौगोलिक दुर्गमता, प्रशासनिक अक्षमता, एवं सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि शासकीय योजनाओं ने भील जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान दिया है, परंतु यह योगदान अपेक्षाकृत सीमित एवं असमान रूप से वितरित है। योजनाओं को अधिक समावेशी, सुलभ, एवं संवेदनशील बनाने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है।

8. सुझाव

8.1 नीतिगत सुझाव

1. **जागरूकता अभियान:** भील जनजाति के बीच शासकीय योजनाओं की जानकारी हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, विशेषकर महिलाओं एवं दूरस्थ क्षेत्रों में।
2. **एकीकृत सेवा वितरण:** विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक एकीकृत एवं समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
3. **सांस्कृतिक संवेदनशीलता:** योजनाओं को भील जनजाति की सांस्कृतिक मान्यताओं एवं परंपराओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
4. **बुनियादी ढाँचे का विकास:** दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र, एवं विद्यालयों का निर्माण किया जाना चाहिए।
5. **आजीविका विविधीकरण:** कृषि के अतिरिक्त अन्य आजीविका विकल्प—जैसे हस्तशिल्प, वनोपज प्रसंस्करण, एवं लघु उद्योग—विकसित किए जाने चाहिए।

8.2 शोध-संबंधी सुझाव

1. भोपाल जिले के अन्य जनजातीय समुदायों (गोंड, सहरिया, आदि) पर भी इसी प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए।
2. शासकीय योजनाओं के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन हेतु अनुदैर्घ्य अध्ययन (Longitudinal Study) किया जाना चाहिए।
3. योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाना चाहिए।
4. भील जनजाति की महिलाओं पर योजनाओं के विशिष्ट प्रभाव का लैंगिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाना चाहिए।

9. शोध का महत्त्व

प्रस्तुत शोध का महत्त्व निम्नलिखित है:

1. **शैक्षणिक महत्त्व:** यह शोध भील जनजाति एवं शासकीय योजनाओं के अंतर्संबंध पर उपलब्ध साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
2. **नीतिगत महत्त्व:** शोध के निष्कर्ष एवं सुझाव नीति-निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक हैं, विशेषकर भोपाल जिले के संदर्भ में।
3. **प्रायोगिक महत्त्व:** शोध क्रियान्वयन एजेंसियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है।
4. **सामाजिक महत्त्व:** शोध भील जनजाति की वास्तविक स्थिति एवं आवश्यकताओं को उजागर करता है, जो सामाजिक न्याय एवं समानता की दिशा में सहायक है।

10. सन्दर्भ

1. Bhandari, K. (2019). भील जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर आधुनिकीकरण का प्रभाव. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, 6(5), 203-210.
2. Dubey, P., & Singh, P. (2025). मध्य प्रदेश राज्य में जनजातियों के कल्याण में शासकीय विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का प्रभाव. *International Journal of Multidisciplinary Trends*, 7(11), 91-95.
3. Government of India. (2024). भारत में जनजातीय कल्याण के लिए सरकारी पहल. *Press Information Bureau*.
4. Government of India. (2024). जनजातीय समाज को सशक्त बनाना: सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पहल. *Press Information Bureau*.
5. Government of India. (2021). *Census of India 2011: Primary Census Abstract*. Office of the Registrar General & Census Commissioner.
6. Government of Madhya Pradesh. (n.d.). जनजातीय कार्य विभाग. tribal.mp.gov.in.
7. IUSSP. (2012). *Janani Surakshya Yojana and its impact on Newborn Care among Bhil Tribe of Madhya Pradesh, India*. International Union for the Scientific Study of Population.
8. IUSSP. (n.d.). *Monetary Intensive and Utilization of Maternal Care among Tribal Population of Central India*. International Union for the Scientific Study of Population.
9. Patel, B. L., & Prajapati, C. L. (2026). अनुसूचित जनजाति की आर्थिक स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन (पन्ना जिले के विशेष संदर्भ में). *International Journal of Reviews and Research in Social Sciences*, 14(1), 64-68.
10. TRIFED. (n.d.). *Home | TRIFED - Tribes India | PMVDY*. Ministry of Tribal Affairs.



11. Government of Madhya Pradesh. (2026). आदिवासी क्षेत्रों के 63 हजार घरों में पहुंचेगी बिजली. *Dainik Bhaskar*.
12. Government of Madhya Pradesh. (2026). MP Cabinet approves Rs 7,133.17 Cr for continuation of Tribal Affairs. *Asian News International*.
13. [Ignca.gov.in](http://ignca.gov.in). (n.d.). मध्य प्रदेश की भील जनजाति. *IGNCA*.
14. Shodhganga. (n.d.). Impact of Government Schemes on Bhil Tribe. inlibnet.ac.in.